



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX
COMMISSIONERATE
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI
BENGALURU- 560300

लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE. NO. 03/2020 - दिनांक / DATED - 24.02.2020

विषय: निर्यात कर्ता द्वारा अनुपालन किये जानेवाले मानक प्रचालन कार्यवाही के संबंध में ।
Sub: Standard Operating Procedure (SOP) to be followed by
Exporters - reg.

सभी नियागतकर्ताओं एवं सीमा शुल्क एजेंट का ध्यान , निर्यात कर्ता द्वारा अनुपालन किये जानेवाले मानक प्रचालन कार्यवाही के संबंध में , सी.बी.आई.सी के दिनांक 23.1.2020 का परिपत्र सं 131/1/2020-GST की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of Exporters and Customs House Agents is invited to CBIC Circular No.131/1/2020-GST dated 23.01.2020, regarding the Standard Operating Procedure to be followed by exporters.

2. पिछले कुछ महीनों में कुछ वस्तुओं के निर्यात के संबंध में समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी) के अधीन प्रतिदाय के तहत कपटपूर्ण रूप से प्राप्त सेनवाट क्रेडिट के मुद्दीकरण एवं अपात्र सेनवाट क्रेडिट प्राप्त करने का कई मामलों का पता कर दिया गया है । उसके सत्यापन में , कई ऐसे निर्यातकर्ता के अनस्तितत्व भी पता लगाया गया । इन सभी मामलों में निवेश कर ऋण का उपयोग जाली बीझक के आधार पर लिया गया एवं ऐसे ऐटीसी को उपयोग करते हुए निर्यात पर लगाने वाले आई.जी.एस.टी का भुगतान किया गया ।

There are several cases of monetisation of credit fraudulently obtained or ineligible credit through refund of Integrated Goods and Service Tax (IGST) on exports of goods detected in the past few months. On verification, several such exporters were found to be non-existent in many cases. In all these cases, Input Tax Credit (ITC) was taken on the basis of fake invoices and IGST on exports was paid using such ITC.

3. जोखिम को कम करने के उद्देश्य से जोखिम मापदण्ड के आधार पर परीक्षण एवं कुछ निर्यात में सुदृढ डाटा विश्लेषण एवं कृत्रिम बुद्धि उपकरण के आधार पर बनाये गए तंत्र के आधार पद आगे का परीक्षण किया जाता है । ऐसे मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने तक प्रतिदाय सूची स्थगित किया जाता है । आगे , ऐसे निर्यातकर्ताओं के निर्यात माल एवं लदाई सीमा शुल्क पोर्ट में 100% सत्यापन किया जाता है ।

To mitigate the risk, measures were taken to apply stringent risk parameters-based checks driven by rigorous data analytics and Artificial Intelligence tools based on which certain exports are taken up for further verification. The refund scrolls in such cases are kept in abeyance till the verification report in respect of such cases is received from field formations. Further, the export consignments/shipments of concerned exporters are subjected to 100% examination at customs port.

4. जोखिम को कम करने के लिए सत्यापन किया जाता है, पर यह भी आवश्यक है कि, वास्तविक निर्यातकर्ता को कोई तकलीफ न हो। इस प्रसंग में, सत्यापन को त्वरित करने के लिए, उन निर्यातकर्ता जिनके स्कॉल स्थगित किया गया है, सी.जी.एस.टी या सीमा शुल्क द्वारा सूचना प्राप्त करते ही या स्वतःपूर्ण रूप से संलग्नित अलुलग्नक 'क' में सूचना को भरना है और यदि कुछ अतिरिक्त सूचना अपेक्षित हो तो उसको भी साथ में भरकर सी.जी.एस.टी प्राधिकारियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना है।

While the verifications are caused to mitigate risk, it is also necessary that genuine exporters do not face any hardship. In this context, to expedite the verification, the exporters whose scrolls are in abeyance, on being informed of the same, either by CGST or Customs, or on their own volition, should fill in information in the enclosed Annexure "A" format, and submit to jurisdictional CGST authorities for verification, along with any additional information, if required.

5. समय सीमाओं को पालन करते हुए, निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने के 14 कार्यदिवस के अंदर क्षेत्रीय सी.जी.एस.टी. कार्यालय द्वारा सत्यापन को समाप्त करना चाहिए। अगर यह सत्यापन 14 कार्यदिवस के अंदर समाप्त नहीं किया गया तो, क्षेत्रीय अधिकारी उसको प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा सृजित नोडल सेल को सूचित करेंगे।

Adhering to the timelines, verification shall be completed by the jurisdiction CGST office within 14 working days of furnishing of information in the proforma by the exporter. If the verification is not completed within this period, the jurisdiction officer will bring it to the notice of the nodal cell which will be constituted in the jurisdictional Pr.Chief Commissioner/Chief Commissioner office.

6. निर्धारित प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करने के 14 दिनों की समयावधि के बाद, संबंधित मुख्य आयुक्त को ई मेल प्रेषित करने के बाद क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के सामने मामले को प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर आगे के 7 कार्यदिवस में सत्यापन को समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई लेना है।

After the 14 days period from the date of submission of details in the prescribed format, the exporter may escalate the matter to the Jurisdictional Pr. Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax by sending an email to the concerned Chief Commissioner. The jurisdictional Pr. Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax should take appropriate action to get the verification completed within next 7 working days.

7. अगर, कोई प्रतिदाय एक महीने तक विलंबित है तो, निर्यातकर्ता अपनी शिकायत को सभी संगत विवरण जैसे जी.एस.टी.एन, आई.ई.सी, लदान बिल सं, निर्यात किये जानेवाले बंदरगाह, एवं सी.जी.एस.टी कार्यालय जहाँ निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत किया गया आदि के साथ www.cbic.gov.in/issue में पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसे सभी शिकायतों का परीक्षण, जी.एस.टी. सदस्य, सी.बी.आई.सी की अध्यक्षता में सृजित समिति द्वारा किया जा सकता है और उसका समाधान भी निकाल सकते हैं।

In case, any refund remains pending for more than one month, the exporter may register his grievance at www.cbic.gov.in/issue by giving all relevant details like GSTIN, IEC, Shipping Bill No., Port of Export and CGST formation where the details in the prescribed format has been submitted etc. All such grievances shall be examined by a Committee headed by Member GST, CBIC for resolution of the issue.

8. उपर्युक्त कार्यवाही के अनुपालन में कोई तकलीफ पायी गयी तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जा सकता है ।

Any difficulties in following the above procedure may kindly be brought to the notice of the undersigned.

संलग्न: Enclosure- अनुलग्नक -कAnnexure -A

अशोक

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

बी.ए.ए.सी तकनीकी फाईल सी सं VIII/48/97/2020 के तहत जारी/ Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रति प्रस्तुत/ Copy submitted to:

- 1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूरु, बेंगलूरु अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन, बेंगलूरु/
The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building ,
Bengaluru

प्रति प्रेषित/ Copy to:

- 1) सभी अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय, बेंगलूरु/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate,
Bengaluru
- 2) फेडरेशन ऑफ कर्नाटका, चेंबर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री(एफ.के.सी.सी.आई) , सं 9996,
केंपेगौडा, रोड, गांधीनगर, बेंगलूरु
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI),
No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
- 3) बेंगलूरु सीमा शुल्क ब्रोकर्स एजेंट्स संगठन, 71, कार्गो विल्लेज, बी-ब्लाकख् बेंगलूरु
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बेंगलूरु
Bangalore Customs Brokers Agents Association, No.71, Cargo Village, B-
Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru
- 4) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पॉर्टर्स संगठन, (एफ.आई.एफ.ओ), पहला तल, वी.आई.टी.सी,
भवन, कस्तूरिबा रोड, बेंगलूरु
Federation of Indian Export Organisation (FIFO),1stFloor,VITC Building,
Kasturba Road, Bengaluru
- 5) बेंगलूरु सीमा शुल्क वेब साईट/Bengaluru Customs Website
- 6) सूचना पट्ट/Notice Board.
- 7) बेंगलूरु में संचालित सभी कोरियर एजेंसी/All Courier Agencies Operating at
Bengaluru
- 8) मास्टर फाईल/ Master file

The details to be provided by the exporter for verification:

I. GST related data:

1. GSTIN –
2. Please provide the following details if the proprietor/director/partner of this entity is also associated with other entities.

S No	Name of Director/Partner/ Proprietor	Name of the other Entity Associated with	PAN (DIN if Director)	GSTIN	Registration status (Active / Inactive)
1					
2					
3					

3. Turnover of previous Financial Year -
(For New Entity till date Current Financial Year Turnover, if any)

4. Details of GST liability–

S No	Return Type	Declared aggregate liability for Previous Financial Year	Declared aggregate liability for Current Financial Year
1	GSTR 3B		
2	GSTR 1		

5. Details of ITC :

FY	ITC available in GSTR-2A	ITC availed in GSTR-3B	Mismatch	Details of payment or reversal of mismatched ITC
2017-18				
2018-19				
2019-20				

6. Details of refund claimed in previous Financial Year and current Financial Year-

S No	GSTIN	Type of Refund	ARN No. and Date	Amount		Authority from which refund claimed
				Claimed	Sanctioned	

7. Summary of E way Bills generated for relevant period.

S No	Supplies	No of E way Bill generated	HSNs	Taxable Amount
1	Inward			
2	Outward			

II. Financial Data

1. Bank Account details including the bank accounts of proprietor/partner/directors—

S. No.	Account Number	IFSC Code	Account Type	Name of Account Holder	PAN of Account Holder	Date of opening of Bank Account

2. Bank Account statement of past 6 months in respect of the bank accounts provided above.
3. BRCs/FIRCs evidencing receipt of foreign remittances against the exports made in past 1 year.
4. Bank letter for up to date KYC of all bank accounts provided above.
5. Top 5 creditors and Debtors (with GSTIN) from account(s) where refunds are proposed to be received and from which major business transactions (payments for supplies and receipts) are carried out.

III. Additional Data

1. Copy of PAN.
2. Copy of IEC
3. Certificate of Incorporation or partnership deed
4. Rent agreement of all premises along with geo-tagged photos
5. Telephone Bill of past 3 months for all premises
6. Electricity Bill of past 3 months for all premises
7. Number of employees and the statement of PF evidencing employees
8. Copy of the following schedules of the latest Income Tax Return:
 - (i) Computation of depreciation on plant and machinery under the Income-tax Act
 - (ii) Computation of depreciation on other assets under the Income-tax Act
 - (iii) Summary of depreciation on all the assets under the Income-tax Act